पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 22, अंक 1-2/2021

कोरोना महामारी के दौरान जैविक उत्पादों की बिक्री और खपत में हुई वृद्धि

करीब 91 प्रतिशत जैविक उत्पाद विक्रेताओं और 89 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना महामारी की प्रथम लहर के दस महीनों में जैविक उत्पादों की बिक्री और खपत में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

जहां वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी पर पूरी तरह से काबू पाने के अथक प्रयास अभी चालू ही है, वहीं अब राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों के खानपान के तरीकों में बदलाव होने के भी संकेत मिल रहे हैं, जो कि जैविक उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में सामने आए हैं। महामारी के दौरान बहुत से खुदरा जैविक उत्पाद विक्रेताओं की अच्छी बिक्री हुई है जो कि कोरोना महामारी के चलते उपभोक्ताओं के खाने की बदलती आदतों में बदलाव के कारण है। कोरोना काल में उपभोक्ता अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जैविक उत्पादों की ओर रुख कर रहे हैं। बढ़ते रुझान नई जीवन शैली की शुरुआत के संकेत भी हो सकते हैं।

उपरोक्त निष्कर्ष 'कट्स' द्वारा राजस्थान के दस प्रमुख जिलों में जैविक उत्पादों की बिक्री एवं उपभोग पर कराए गए एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण सर्वेक्षण में सामने आए हैं। करीब 90 फीसदी उपभोक्ताओं ने माना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए जैविक उत्पादों का उपभोग लाभदायक है और इस दृष्टि से जैविक उत्पादों के उपभोग की प्रवृत्ति भी बढ़ी है।

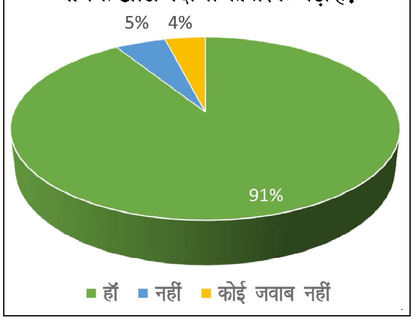

सर्वेक्षण में यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि उपभोक्ताओं ने इस कोरोना काल में कौन-कौन से जैविक उत्पादों की मांग विक्रेताओं के सम्मुख रखी और कौन-कौन से उत्पादों की ज्यादा बिक्री हुई। सर्वेक्षण में करीब 86 फीसदी उपभोक्ताओं का मानना है कि भविष्य में जैविक उत्पादों की खपत और उपभोग दोनों ही बढ़ेंगे।

सर्वेक्षण में करीब 72 फीसदी उपभोक्ताओं का मानना है कि जैविक उत्पाद गैर-जैविक उत्पादों की अपेक्षा ज्यादा महंगे हैं। सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश उपभोक्ताओं को लगता है कि उनके लिए जैविक खाद्य पदार्थ खरीदना मुश्किल है। बावजूद इसके सर्वेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह रही कि कोरोना महामारी के बीच जैविक उत्पादों की आमद भी अधिक रही और खपत भी अधिक हुई है।

सर्वेक्षण में 89 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने कहा कि उन्होंने जैविक उत्पादों का उपभोग करना शुरू कर दिया है। इन 89 में से 54 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं के जागरूकता अभियान से जैविक उत्पाद उपभोग करने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। करीब 60 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने यह महसूस किया कि उन्हें जैविक उत्पादों की दुकानें/आउटलेट्स तलाश करने में भी काफी परेशानी आई।

सर्वेक्षण में करीब 91 प्रतिशत विक्रेताओं का कहना है कि कोरोना काल के 10 महीनों में जैविक उत्पादों की बिक्री और मांग में वृद्धि हुई है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में 62 फीसदी में से 55 फीसदी विक्रेताओं ने बताया कि वे जैविक उत्पाद सीधे किसानों से खरीदते हैं। जबकि 45 प्रतिशत ने कहा कि वह वितरकों और अन्य स्रोतों से जैविक उत्पाद खरीदते हैं।

कोरोना काल में जैविक उत्पादों में उपभोक्ता की पसंद के संबंध में 74 फीसदी विक्रेताओं ने बताया कि जैविक उत्पादों में सब्जियों की मांग अधिक रहती है। जबकि 6 प्रतिशत फलों,13 प्रतिशत अनाज और एक प्रतिशत जैविक मसालों की मांग रही है।

करीब 46 प्रतिशत विक्रेताओं का मानना है कि उपभोक्ता जैविक उत्पादों की खरीद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करते हैं। जबकि 52 फीसदी विक्रेताओं का कहना है कि उपभोक्ता जैविक उत्पाद खरीदने के लिए सीधे विक्रेताओं के पास आते हैं।

सर्वेक्षण से उभरकर सामने आया कि अब लोग खानपान के मामले में एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे जैविक उत्पादों के उपभोग और बिक्री दोनों में बढ़ोतरी होगी ।

कोरोना काल के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए यह साफ है कि सरकार को जैविक खेती को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। किसान जैविक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाएं, विक्रेता जैविक वस्तुओं के विक्रय को प्रमुखता दें और उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जैविक पदार्थों के उपभोग को ज्यादा महत्व दें।

इस अंक में...

अपात्र लोगों ने उठाए गरीब किसानों के रुपए ... 3
आम बजट 2021-22 की प्रमुख घोषणाएं 6
सस्ती बनाकर खरीदनी होगी महंगी बिजली ... 8
भूजल गड़बड़ाने से बढ़ा पेयजल संकट 9
प्रदेश में बढ़ गई महिला अपराध की घटनाएं ... 10

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आयोजित परिचर्चा

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के साथ ही जैविक खेती के प्रचार प्रसार पर दिया जोर

''प्लास्टिक हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है, जिसके नकारात्मक पर्यावरणीय परिणाम सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खेती में बढ़ते रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मानव जीवन संकट में है। इनके बढ़ते गंभीर दुष्परिणामों से निपटने के लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे।''

'कट्स' द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एवं प्रो-ऑर्गेनिक परियोजना के तहत आयोजित वार्षिक राज्य स्तरीय परिचर्चा में यह उभरकर सामने आया। परिचर्चा के प्रारंभ में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 15 मार्च का दिन अब सम्पूर्ण विश्व में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने एवं उपभोक्ता आंदोलन को संगठित करने का वार्षिक उत्सव बन चुका है।

'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने अपने उद्बोधन में विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि किस तरह प्लास्टिक के उपयोग से सम्पूर्ण विश्व के पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कार्यक्रम में राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर के निदेशक डॉ. ए.एस. बलोदा ने परम्परागत कृषि विकास परियोजना के तहत सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने और हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए सामूहिक रूप से जैविक खेती की मुहिम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

पदमश्री पुरस्कार प्राप्त किसान जगदीश पारीक ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि किस प्रकार जैविक खेती से किसान काफी अच्छा फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने बताया अब जैविक वस्तुओं की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कार्यक्रम के दौरान 'कट्स' के राजदीप पारीक ने प्रो-ऑर्गेनिक परियोजना के तहत की गई विभिन्न गतिविधियों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया। कार्यक्रम में कृषि अनुसंधान अधिकारियों, विशेषज्ञों, किसानों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित 60 से अधिक भागीदारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

जैविक खेती और जैविक पदार्थों का उपभोग आज की अहम जरूरत

प्रो-ऑर्गेनिक परियोजना के अन्तर्गत 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा जयपुर स्थित विनोबा ज्ञान मंदिर, बापू नगर में 08 मार्च, 2021 को जैविक उत्पादों के मेले का आयोजन किया गया। मेले का औपचारिक उद्घाटन 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन और प्रमुख प्रगतिशील किसान गंगाराम सेपट द्वारा किया गया।

इस अवसर पर 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि जैविक खेती और जैविक पदार्थों का उपभोग आज की जरूरत बनता जा रहा है। मेले का उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं को आमने सामने परिचय कराना है, जिससे किसानों को ना केवल प्रोत्साहन मिले बल्कि उपभोक्ताओं और किसानों के बीच एक चैनल भी बन सके।

मेले के शुभारंभ में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने बताया कि उपभोक्ता यह जान गए हैं कि खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग उनकी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। भविष्य में महामारी के परिणामों को देखते हुए जैविक खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ेगी जो कि किसानों व उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद साबित होगी।

इस अवसर पर गंगाराम सेपट ने कहा कि अक्सर जो किसान जैविक खेती अपनाते हैं उनको अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसे मेलों के आयोजन से जैविक खेती करने वाले किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा, साथ ही उन्हें प्रोत्साहन भी मिलेगा।

मेले में जयपुर जिले के प्रगतिशील किसानों के अतिरिक्त जैविक उत्पाद विक्रेताओं ने भी विभिन्न जैविक खाद्य पदार्थों की स्टाल्स लगाई। यह देखा गया कि मेले में उपभोक्ताओं ने काफी रुचि दिखाई और सब्जियों, फलों और अन्य जैविक खाद्य पदार्थों की जमकर खरीददारी की।

आवास योजना में किया दोहरा भुगतान

गांवों में गरीबों को आवास देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लाभार्थियों को दोहरे भुगतान के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 2016-17 से 2018-19 तक योजना की क्रियान्विति के दौरान 439 मामलों में लाभार्थियों को आवास राशि की किश्तों का दोहरा भुगतान कर दिया गया।

बड़ी बात यह है कि ममला पकड़ में आने के चार साल बाद तक भी जिलों में प्रशासनिक मशीनरी करीब दो करोड़ रुपए की इस दोहरे भुगतान की पूरी वसूली नहीं कर पाई है। हाल ही ग्रामीण विकास सचिव के.के.पाठक द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रदेशभर के जिलों में ऐसे अनियमित भुगतान के प्रकरणों को सामने लाया गया। *(रा.प., 19.06.21)*

शिक्षा निदेशालय में लैपटॉप हुए खुर्द-बुर्द

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में 48 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। मामला तब उजागर हुआ जब तत्कालीन स्टोर कीपर कैलाश ओझा का चार्ज अन्य किसी कार्मिक को देने के आदेश हुए। चार्ज लेनदेन में 6 एयर कंडीशनर, लैपटॉप, कम्प्यूटर, स्टेशनरी वितरण आदि में भारी अनियमितता की आशंका होने पर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया।

कमेटी ने जांच में पाया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सामग्री में करीब 23 लाख रुपए के सामान का स्टॉक रजिस्टर में इंद्राज ही नहीं किया गया। इसी तरह भुगतान में छेड़छाड़ कर तीन साल में करीब 14.50 लाख रुपए की हानि पहुंचाने का मामला भी सामने आया। मामले में दोषी कैलाश ओझा और प्रभारी अधिकारी बसंत किराडू के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। *(रा.प., 08.02.21)*

हजम नहीं कर पाए राशन का गेहूं

प्रदेश के करीब 82 हजार सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं और चना हजम नहीं कर पाए। रसद विभाग द्वारा उनसे गैर वाजिब तरीके से दो रुपए प्रति किलो की दर से उठाए गए गेहूं की 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली कर भरपाई की जा रही है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का राशन खाने वाले राज्य कर्मचारियों से वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीब 49 हजार कर्मचारियों से 64.79 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। जबकि अभी करीब 33 हजार कर्मचारियों से वसूली बाकी है। इनसे भी वसूली के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ऐसे में वसूली का आंकड़ा 100 करोड़ रुपए के पार जाने का अनुमान है। *(रा.प., 30.04.21)*

अभी भी लाखों लगा रहे हैं अंगूठा

अभी भी प्रदेश में 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 4 लाख 20 हजार पुरुष और महिलाएं अनपढ़ हैं। इनमें पुरुषों का आंकड़ा एक लाख 15 हजार है। वहीं अनपढ़ महिलाओं की संख्या 3 लाख 5 हजार है। यह सभी अभी भी कागजों पर अंगूठा लगा रहे हैं। इनमें ज्यादातर ग्रामीण पुरुष और महिलाएं हैं।

इससे जाहिर है कि करीब 20 सालों से हर साल सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर साक्षरता के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। अभियान कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। इस बार फिर पंचायत स्तर पर समितियों का गठन कर साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान पर अपनी नजर रखें और निरक्षरता के कलंक से मुक्ति पाएं। *(रा.प., 04.01.21)*

कई कंपनियों पर लग गए ताले

कोरोना महामारी के चलते बिगड़ी अर्थव्यवस्था के कारण अप्रेल 2020 से फरवरी 2021 तक 10113 रजिस्टर्ड कंपनियां बंद हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा दिल्ली में 2400 व राजस्थान में 500 व मध्यप्रदेश में 111 कंपनियों ने अपना काम समेट लिया। केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में संसद में यह जानकारी दी।

गौरतलब है कि पिछले साल देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ा था। करीब छह माह तक लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थीं। भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि कंपनी कानून 2013 के सेक्शन 248(2) के तहत फरवरी 2021 तक देश में 10113 कंपनियों ने स्वेच्छा से अपना कारोबार बंद करने का फैसला किया है। *(रा.प., 10.03.21)*

करोड़ों टन खाना फेंक देती है दुनिया

दुनिया में हर साल करीब 93.10 करोड़ टन खाना बर्बाद हो जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में यह खुलासा हुआ है। यह दुनिया के कुल खाने का करीब 17 फीसदी है। घरों, संस्थानों, रिटेल आउटलेट्स, रेस्टोरेंटस आदि में खाना बेकार जाता है। घरों में सबसे ज्यादा खाना फेंका जाता है।

जारी रिपोर्ट के अनुसार हर साल अफगानिस्तान में 82, पाकिस्तान में 74, श्रीलंका में 76, नेपाल में 79 किलो खाना प्रति व्यक्ति बर्बाद होता है। दक्षिणी एशिया में भारत में बर्बाद होने वाले खाने का औसत 50 किलो प्रति व्यक्ति है। करीब-करीब सभी देशों में यह बर्बादी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2019 में करीब 69 करोड़ लोग भूख से प्रभावित हुए। कोरोना महामारी से यह आंकड़ा और अधिक बढ़ने के आसार हैं। *(रा.प., 06.03.21)*

अपात्र लोगों ने उठाए गरीब किसानों के रुपए

केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश में पहली से छठी किस्त तक 44 लाख 40 हजार 462 अपात्र लोगों ने 62 अरब 16 करोड़ 64 लाख 68 हजार रुपए गरीब किसानों के हड़प लिए। इतना ही नहीं प्रदेश के 70 हजार आयकरदाताओं ने भी किसानों के हक के 100 करोड़ रुपए हड़प लिए।

मामले का खुलासा तब हुआ जब केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की टीमों ने किसानों के आधार कार्ड नंबर व पैन नंबर से उनके दिए गए बैंक खातों का वेरीफिकेशन किया। इसमें खाताधारक व खेत के मालिकों के नाम में अंतर पाया गया। किसान सम्मान निधि योजना में सालाना 6000 रुपए का लाभ दिया जाता है। गरीब किसानों की राशि हड़पने वालों में कई करोड़ोंपति लोग हैं और उनके बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं। अब हड़पी गई राशि की ऐसे लोगों के बैंक खातों को फ्रीज कर वसूली होगी। *(दै.भा., 20.03.21)*

अमीर व गरीब के बीच बढ़ी खाई

कोरोना महामारी ने गरीब व अमीर के बीच की खाई को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के दौरान जहां अमीर मालामाल हो गए तो वहीं गरीब और ज्यादा कंगाल हो गए। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने 'इनइक्वालिटी वायरस' रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक देश के अरबपतियों की संपत्ति 35 फीसदी तक बढ़ गई है। वहीं, करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी छिन गई और उनके खाने के लाले पड़ गए।

महामारी से पिछले 100 वर्षों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट व 1930 की महामंदी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ। यह असमानता सिर्फ भारत में ही नहीं हुई, दुनिया के प्रमुख देशों में भी देखने को मिली है। रिपोर्ट में 79 देशों के 295 अर्थशास्त्रियों की राय व अरबपतियों की संपति का विश्लेषण किया गया है। *(रा.प., 26.01.21)*

खरीदी महंगे दाम पर आयुर्वेदिक दवाएं

प्रदेश के आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों ने बाजार से 10 गुना अधिक कीमत पर दवाएं खरीदी फिर एक ऐसी लैब से जांच कराई जिसके पास आयुर्वेदिक दवाओं की जांच के लिए न तो उपकरण थे और न ही माइक्रो बायलॉजिस्ट। हद तो यह है कि लैब ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को दे दी और उन दवाओं को आयुर्वेदिक अस्पतालों में भेज भी दिया गया।

बड़ा सवाल यह है कि जब कंपनी के पास जांच की मशीनें ही नहीं है तो फिर दवा की जांच कैसे हो गई और रिपोर्ट विभाग को कैसे भेज दी गई। जबकि आयुर्वेद विभाग की क्रय समिति ने खुद माना है कि कंपनी द्वारा दवाइयों की जांच के लिए जो उपकरणों की सूची दी गई, उनमें कोई भी उपकरण आयुर्वेद औषधियों की जांच के नहीं है। *(दै.भा., 20.02.21)*

आपदा को अवसर नहीं बना पाए अफसर

राज्य में 13 लाख प्रवासियों समेत 50 लाख से अधिक मजदूरों को उनके कौशल के अनुसार प्रशिक्षण और लगभग ठप हो चुके 1.75 लाख छोटे-बड़े उद्योगों में उत्पादन की बहाली..।

कोरोना में पैदा हुई इन चुनौतियों के बारे में नेताओं और अफसरों की जुबान पर यह जुमला जोर शोर से चढ़ा कि हम आपदा को अवसर बनाएंगे। लेकिन 10 माह के बाद भी नतीजे असरदार नजर नहीं आ रहे।

उद्योगों में बड़ी इकाइयां तो फिर भी इस आपदा से निकल कर वापस खड़ी हो गई लेकिन छोटी-मझोली इकाइयों पर मार बरकरार है। इनके ताजा हालात और उत्पादन को लेकर खुद उद्योग विभाग आश्वस्त नहीं है। इधर, कौशल रोजगार के मोर्चे पर तो समूची कवायद अभी तक कागजों से ही नहीं निकल पा रही हैं। *(रा.प., 08.01.21)*

स्कूलों की दोहरी फीस से दबे अभिभावक

कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे अभिभावकों को इस सत्र में पढ़ाई का अतिरिक्त भार ढोना होगा। अभिभावकों को पिछले सत्र 2020-21 की पूरी फीस तो देनी ही होगी साथ ही इस सत्र 2021-22 की फीस भी स्कूलों को देनी होगी। अगर एक घर में दो बच्चे हैं तो एक से डेढ़ लाख रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

इसका सबसे ज्यादा फर्क मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। इससे उनका घर का खर्च गड़बड़ाएगा। कई परिवार तो ऐसे भी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में स्कूलों की फीस ही नहीं भरी। कई परिवार ऐसे भी थे जो 70 फीसदी फीस जमा करा चुके थे। अभिभावकों का कहना है कि पहले ही कोरोना के आर्थिक संकट से परेशान हैं। ऐसे में अब स्कूल फीस का दोहरा भार पड़ रहा है। *(रा.प., 12.02.21)*

प्रदेश में बेपटरी हो रही उच्च शिक्षा

वोट बैंक को लुभाने के लिए सरकार की ओर से लगातार उपखंड मुख्यालयों पर नए राजकीय कॉलेज खोले जा रहे हैं। लेकिन ये कॉलेज संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। एक तरफ पहले से ही संचालित कॉलेजों में ही पर्याप्त स्टाफ नहीं है, वहीं 50 से अधिक नए कॉलेज और खोलने से उच्च शिक्षा विभाग की शैक्षिक व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई है।

फिलहाल प्रदेश में प्राचार्य के 153 व सह व सहायक आचार्य के 2579 पद खाली हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के एक लाख से भी ज्यादा बेरोजगारों को कॉलेजों में भर्ती का इंतजार है। *(रा.प., 11.03.21)*

बीमा राशि के लिए भटक रहे परिजन

कोरोना की पहली लहर से अब तक हजारों वॉरियर्स कोविड ड्युटी में अपनी जान गंवा चुके। ऐसे वॉरियर्स के लिए केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपए के बीमा की घोषणा की थी। लेकिन तमाम औपचारिकताओं के बीच आज भी बड़ी संख्या में प्रदेश के ऐसे मृतक वारियर्स के परिजन बीमा राशि के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

कई मामलों में परिजनों को कोविड ड्युटी सबूत के दस्तावेज और मृत्यु के प्रमाण-पत्र तक आसानी से नहीं मिल पा रहे। इन हालातों के चलते मृतकों के परिजनों को बीमा राशि भुगतान नहीं मिल पा रहा। कुछ मामलों में यह भी सामने आया है कि मृतकों के परिजन जब संबंधित अधिकारियों से मिलते हैं तो उन्हें सरकारी प्रक्रिया में समय लगने की बात कह कर टरका देते हैं। *(रा.प., 19.06.21)*

कर्मचारी खा गए गरीबों का गेहूं

प्रदेश के 20 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मियों के परिवारों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में दो रुपए किलो कीमत पर गेंहू उठाने के मामलों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश पर जिला कलेक्टरों ने 5000 से ज्यादा कर्मचारियों को वसूली के नोटिस थमाए हैं।

अभी नोटिस देने का यह सिलसिला जारी है और जिला स्तर पर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अब इन कर्मचारियों से 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली करेगा। गौरतलब है कि यह योजना 2013 में शुरू हुई थी। प्रदेश में सात वर्षों से नियमों के विपरीत सरकारी कर्मी गरीबों का गेहूं खा रहे थे। *(दै.भा., 03.01.21)*

सतत् विकास लक्ष्यों की योजना

हम दुनिया का कायाकल्प करने की दहलीज पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक सम्पन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाएगा।

गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर, उपभोग व उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी।

सतत विकास पैमाने में जयपुर ग्रीन जोन में

स्वास्थ्य के पैमाने के अलावा अन्य सभी सूचकांकों में जयपुर ग्रीन जोन में है। सरकार की ओर से जारी सतत विकास लक्ष्य 2020 की रैंकिंग में जयपुर ने 12 में से 8 पैमानों पर प्रथम स्थान हासिल किया है। राज्य की बात करें तो जिलों में झुंझनूं के बाद जयपुर दूसरे नंबर पर है। राज्य में विकास की दौड़ में झुंझनूं जिला सिरमौर रहा है।

एसडीजी इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में जयपुर जिला 69.36 अंक हासिल कर दूसरे नंबर पर है। समग्र रूप से 12 विकास सुचकांकों के आधार पर तैयार इस रैंकिंग में जयपुर ने 12 में से 8 लक्ष्यों में 100 में से 60 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। बारह में से चार सूचकांकों पर जयपुर ने 60 से कम अंक प्राप्त किए हैं। इनमें से तीन सूचकांक स्वास्थ्य से जुड़े हैं। एक झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों से संबंधित है। चार में से तीन पैमानों में जयपुर ग्रीन जोन में हैं।

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच वैश्विक विकास के समझौते के तहत भारत समेत 193 देश शामिल हैं। इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर राजस्थान में लक्ष्य निर्धारित किए गए। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 2030 तक की समयावधि तय की गई है। *(रा.प., 14.02.21, 18.02.21)*

सतत विकास लक्ष्य स्कोर में हुआ सुधार

देश में कुल मिलाकर सतत विकास लक्ष्यों के स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है। यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो साफ पानी और स्वच्छता तथा सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा के बारे में अनुकरणीय देशव्यापी प्रदर्शन है।

पिछले दिनों नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया। यह इंडेक्स व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का दस्तावेजीकरण और उनकी रैंकिंग निर्धारित करता है। यह सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी प्रगति की निगरानी का प्राथमिक टूल बन गया है।

इससे राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि यह रिपोर्ट सतत विकास के प्रयासों के दौरान हमारे द्वारा बनाई गई मजबूत साझेदारी को दर्शाती है। हमने 2030 एजेंडा को प्राप्त करने की दिशा में एक तिहाई यात्रा पूरी कर ली है और आगे के प्रयास जारी है।

सतत विकास में कोटा ने छीना ताज

संयुक्त राष्ट्र के गरीबी, भुखमरी उन्मूलन जैसे विषयों पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को लेकर जिलों की रैंकिंग में बड़ा उलटफेर सामने आया है। एक साल में ही कोटा ने लंबी छलांग लगाकर झुंझनूं से सिरमौर का ताज छीन लिया है। वर्ष2021 की रैंकिंग में कोटा 100 में से सर्वाधिक 65.28 अंक हासिल कर बीते वर्ष की छठवीं रैंक से पहली पर आ गया है। जबकि 2020 में अव्वल रहा झुंझनूं तीसरे नंबर पर चला गया है।

सरकार ने वर्ष 2021 के लिए राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2.0 (2021) जारी कर दी है। इसमें आधारभूत ढांचा विकास और प्रशासनिक नजरिए पर तुलनात्मक तौर पर बेहतर जयपुर जिले की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में और गिर गई है। वह दूसरे स्थान पर था, इस बार नौवें नंबर पर लुढ़क गया है। चूरू दूसरी रैंक हासिल करने वाला जिला बन गया है। *(रा.प., 03.04.21)*

भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित

जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। जर्मनी स्थित पर्यावरण संबधी थिंकटैंक 'जर्मन वाच' द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दुनियाभर में दिखाई दे रहा है, लेकिन विकासशील देशों में रहने वालों पर इसका अधिक असर पड़ा है।

जर्मन वाच के डेविड एक्सटीन ने कहा है कि जटिल मौसम संबंधी घटनाओं से गरीब देश उनके परिणामों से जूझने की चुनौतियों का सर्वाधिक सामना करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2000 से 2019 के बीच सर्वाधिक प्रभावित दस देशों में से आठ विकासशील देश हैं, जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। वर्ष 2019 में प्रभावित देशों में भारत सातवें स्थान पर रहा है। *(रा.प., 26.01.19)*

कोरोना से बढ़ रही है भारत में गरीबी

बीते एक साल से कारोना माहमारी ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना महामारी का प्रकोप अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी द्वारा लाए गए वित्तीय संकट के चलते भारत में गरीबों की संख्या 13.4 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो मंदी से पहले 5.9 करोड़ की अपेक्षा दोगुना से भी अधिक है।

विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय संकट से लगभग 3.2 करोड़ भारतीय मिडल क्लास से बाहर हो गए हैं। नौकरी गंवाने की वजह से करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। रिपोर्ट कहती है कि इससे अमीर और गरीब के बीच खाई ज्यादा बढ़ जाएगी और आंशिक रूप से गरीबी को कम करने में भारत की सफलता पर पानी फिर सकता है।

(रा.प., 20.03.21)

आम बजट 2021-22 की प्रमुख घोषणाएं

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट प्रस्तुत किया। कोरोना महामारी से सबक लेकर वित्त मंत्री ने आपदा को एक अवसर माना है। मद्देनजर, बजट में जन स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। कृषि क्षेत्र को ग्रोथ का इंजन मानते हुए पेट्रोल, डीजल सहित 12 चीजों की कस्टम ड्यूटी पर कृषि सेस लगाया है। इससे होने वाली आय कृषि के ढांचागत विकास को मजबूती देगी।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास

कोरोना संक्रमण से बेहाल देश की अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जहां बड़े कल कारखानों को बजट में सम्बल प्रदान किया गया है, वहीं छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों के लिए बड़ा पिटारा भी खोला गया है। सबसे बड़े प्रोजेक्ट पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के तहत 64 हजार करोड़ से भी ज्यादा राशि रखी गई है।

वहीं 40 हजार करोड़ रुपए गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए और 15 हजार 700 करोड़ रुपए का प्रावधान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए किया गया है। यह प्रावधान पिछले साल से दोगुना है। माना जा रहा है कि इससे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान भी रखा गया है।

किसान को माना ग्रोथ इंजन

केंद्रीय बजट में सबसे बड़ा लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। इसके लिए कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और इससे जुड़े कामों के लिए बजट में 2.83 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक लाख 48 हजार 301 करोड़ रुपए इस बार कृषि एवं कृषक कल्याण के लिए खर्च होंगे। किसानों को 16.50 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था में भी सुधार किया है, जिससे किसानों को सभी प्रकार की जिंसों के मामले में उत्पादन लागत का डेढ़ गुना कीमत मिल सके।

बाल विकास एवं महिलाओं पर फोकस

केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए चलाई जा रही विशिष्ट योजनाओं के लिए 28 हजार 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्टार्टअप इण्डिया के तहत महिलाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।

उज्ज्वला योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 9 करोड़ तक कर दिया गया है। महिलाओं को हर प्लेटफॉर्म पर काम करने की आजादी होगी। स्कूलों में बच्चों के मिड-डे मील का बजट 11 हजार 500 रुपए किया गया है। महिला एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के प्रयासों को तेज किया जाएगा। इसके लिए अलग से बजट में प्रावधान किया गया है।

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को दी अहमियत

बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 93 हजार 224 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानकों के तहत 15 हजार सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारी जाएगी। ये स्कूल, दूसरे स्कूलों के लिए उदाहरण बनेंगे। देश में सौ नए सैनिक स्कूल भी स्थापित होंगे।

पूर्व में घोषित भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग को इस साल कानूनी जामा पहनाया जाएगा। देश में नवाचार के लिए नौ शहरों में अम्ब्रेला संस्थाए बनाई जाएंगी। इससे उच्च शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। शिक्षा मिशन के लिए 34 हजार 200 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है। आयोग के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय मदद भी दी जाएगी।

हुनर से पनपेंगे रोजगार के अवसर

कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों के महापलायन पर नजर रखते हुए केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टल की घोषणा की गई है। जिसके जरिए विशाल श्रम शक्ति की सूचनाएं एकत्रित कर उन्हें कौशल विकास, आवास और बीमा जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कौशल विकास में सरकार अन्तरराष्ट्रीय सहयोग पर आगे बढ़ेगी।

जापान और अन्य देशों से कुशलता व उन्नत प्रशिक्षण के लिए सहयोग लिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए चुनिंदा 13 सेक्टरों के लिए 1.97 लाख करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। मनरेगा का बजट भी 15.8 फीसदी बढ़ाया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन : साफ आबोहवा

केंद्रीय बजट में स्वच्छता और पोषण को खास तवज्जो दी है। क्योंकि, स्वच्छ भारत से ही स्वस्थ भारत का निर्माण संभव है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर वर्ष 2021 से 2026 तक 5 वर्षों में एक लाख 41 हजार 678 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्लम मैनेजमेंट, वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट और शहरी निर्माण से कचरे के प्रबंधन पर खास फोकस रहेगा।

इसके साथ ही दस लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरों की हवा को साफ करने पर दो हजार 217 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे लोगों को स्वच्छ आबोहवा मिल सकेगी। वित्तमंत्री ने 64 हजार 184 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन योजना का ऐलान किया है।

मजबूत होगा सेहत का तंत्र

आम बजट में जन स्वास्थ्य को खास अहमियत दी गई है। जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए इस बार 2 लाख 23 हजार 846 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह पिछले बजट के मुकाबले 137 फीसदी ज्यादा है। इससे 6 वर्ष के लिए 'प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना' संचालित की जाएगी जिस पर 64 हजार 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

माना जा रहा है कि इससे सेहत के तंत्र को मजबूती मिलेगी। आमजन तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी। बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही आपदा से निपटने के लिए पहली बार 30 हजार करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड का भी प्रावधान बजट में रखा गया है। कोरोना से बने आर्थिक हालात को देखते हुए यह एक अच्छी पहल है।

राज्य विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर एकनजर

राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट रखा। बजट में करीब-करीब सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बजट में स्वास्थ सुविधाओं का विस्तार करने, किसानों की आय बढ़ाने, शिक्षा क्षेत्र को ज्यादा तवज्जह देने, औद्योगिक ढांचे को विकसित करने, युवा संबल योजना को बेहतर बनाने, बुनियादी ढांचे का विकास करने, सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने और खाद्य वस्तुओं में मिलावट पर सख्त सजा का प्रावधान करने जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सभी वर्गों की झोली खुशियों से भरने का प्रयास किया गया है।

स्वास्थ सुविधाओं का होगा विस्तार

कोरोना महामारी के दौरान सामने आई चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने बजट में 10 हजार 171 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने का प्रावधान रखा है। राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को आगे लाने की कोशिश की जाएगी। राइट टू हेल्थ बिल लाया जाएगा। पहली बार यूनिवर्सल हेल्थ बीमा लागू किया जाएगा। इसके तहत हर परिवार को 850 रुपए में पांच लाख रुपए का चिकित्सा बीमा मिलेगा।

निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ेगा। जयपुर के गणगौरी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

बजट किसानों पर केन्द्रित

मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष से अलग से कृषि बजट की शुरुआत करने की घोषणा करते हुए बजट में कृषक एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है। बजट में 16 हजार करोड़ रुपए के ब्याजमुक्त फसली ऋण वितरित करने का प्रावधान है। इसमें मत्स्यपालकों व पशुपालकों को भी शामिल किया जाएगा। तीन लाख किसानों को निःशुल्क बायो-फर्टिलाइजर और बायो एजेंट दिए जाएंगे। एक लाख 20 हजार किसानों को स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर देने की भी घोषणा की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में घोषित जीरो बजट नेचर फार्मिंग योजना के तहत तीन साल में 60 करोड़ रुपए खर्च कर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। बजट में 50 हजार किसानों को सोलर पंप, 50 हजार किसानों को कृषि कनेक्शन देने एवं जोबनेर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना, हनुमानगढ़ में नए कृषि महाविद्यालय खोले जाने की भी घोषणा की गई है।

शिक्षा को दी अहमियत

प्रदेश के बजट में इस वर्ष शिक्षा के लिए 13 हजार 309 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण स्कूलों के बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बजट में बैक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत सभी राजकीय स्कूलों के कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को मुफ्त स्कूल ड्रेस दी जाएगी एवं कक्षा छह से आठ तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी दी जाएगी।

बजट में 50 नए सरकारी स्कूल खोलने, 100 स्कूलों को क्रमोन्नत करने, 3500 स्कूलों में आधारभूत ढांचागत विकास और 15 स्कूलों में भवन निर्माण के प्रस्ताव भी शामिल हैं। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय व जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग का डीम्ड विश्वविद्यालय, 10 नए सरकारी कॉलेज एवं 12 कन्या कॉलेज खोले जाएंगे।

बाल विकास एवं महिलाओं पर फोकस

बजट में 430 करोड़ रुपए का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए किया गया है। महिलाओं की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने और उनकी काउंसलिंग करने के लिए जयपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिलाओं को निःशुल्क दवा योजना में मुफ्त सैनेटरी नैपकिन देने की घोषणा की गई है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राजीविका के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से निर्मित सामग्री की एक लाख रुपए तक की सीधी खरीद का प्रावधान अमृता सोसायटी की तर्ज पर होगा।

औद्योगिक ढांचा होगा विकसित

कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म, छोटे और मंझोले उद्योगों और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र को उबारने के लिए सरकार ने सीधे वित्तीय राहत का पिटारा खोला है। उद्योग विभाग के लिए बजट में 315 करोड़ 26 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। बजट में सूक्ष्म, छोटे और मंझोले दर्जे के उद्योगों के लिए नई एमएसएमई नीति लाने की घोषणा भी की गई है।

इसके तहत जो युवा खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें आसानी से पांच लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। एक अन्य बड़ी घोषणा में सरकार ने बुनकर, दस्तकार, कुटीर और लघु श्रेणी के उद्योगों पर वर्ष 2000 तक बकाया वे सभी ऋण माफ कर दिए हैं, जो उद्योग विभाग ने विभिन्न योजनाओं में दिए थे।

बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस

राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इस बार बजट में 42071 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। घर-घर पानी पहुंचाने के साथ 12 अन्य नई पेयजल परियोजनाओं पर 6410 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। नई ऊर्जा नीति, कृषि विद्युत वितरण कंपनी के गठन के अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में 18943 करोड़ 23 लाख रुपए का प्रावधान बिजली तंत्र के सुधार के लिए प्रस्तावित है।

आवास विकास के लिए भी बजट में 8776 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। गांवों और शहरों में सड़कों का विकास नई सड़क नीति के तहत किया जाएगा। प्रदेश के 27 राजमार्गों पर 3880 करोड़ रुपए से विकास कार्य शुरू होंगे। कई पंचायतों को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने, शहरी व ग्रामीण विकास में सड़क, ड्रेनेज, शौचालय आदि के मरम्मत के कामों को भी बजट का हिस्सा बनाया गया है।

सस्ती बनाकर खरीदनी होगी महंगी बिजली

घर की छत पर सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन करने के बावजूद डिस्काम से महंगी बिजली खरीदने के सरकारी ड्राफ्ट ने लाखों लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो10 किलोवॉट से ज्यादा क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लॉट लगाना चाह रहे हैं।

सरकार के इस ड्राफ्ट में रूफटॉप सोलर प्लॉट लगाने वाले ऐसे उपभोक्ताओं को न केवल नेट मीटरिंग व्यवस्था खत्म करना प्रस्तावित कर दिया है, बल्कि डिस्कॉम को बिजली बेचने की दर को भी बाजार खरीद से जोड़ दिया है। यानी, खुद के सोलर प्लांट से सस्ती बिजली बनाने के बावजूद उपभोक्ता को बिजली कंपनियों से महंगी दर पर बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा।

हालांकि, इस मामले में न्यू एवं रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, अक्षय ऊर्जा निगम और ऊर्जा विभाग को साफ कर चुका है कि इस पर ऊर्जा मंत्रालय स्तर पर समीक्षा की जा रही है। *(रा.प., 08.03.21)*

सौर ऊर्जा से बचत भी और कमाई भी

लोगों में सोलर प्लांट को लेकर रुझान बढ़ रहा है। इससे उपभोक्ता को दोहरा फायदा हो रहा है। एक तो हर महीने बिजली बिल से निजात मिल गई और वहीं घरेलू उपभोग के बाद बची बिजली जयपुर डिस्कॉम को बेचकर हर महीने कमाई भी कर रहे हैं। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिल रही है।

जयपुर शहर में 2918 सोलर बिजली घरेलू उपभोक्ता हैं। यह हर माह 21.91 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इनमें से 1976 उपभोक्ता घरेलू उपभोग के बाद 6.56 लाख यूनिट बिजली जयपुर डिस्कॉम को बेचते हैं। जिससे 20 लाख रुपए की आमदनी हर महीने हो रही है। इसके अलावा 29 सरकारी विभागों में, 112 इंडस्ट्रियल तथा 751 सोलर कनेक्शन नॉनडोमेस्टिक हैं। इनसे हर माह क्रमशः 2.06 लाख यूनिट, 3 लाख यूनिट और 17.09 लाख यूनिट बिजली उत्पादन हो रहा है। सौर ऊर्जा संयत्र वन टाइम इनवेस्टमेन्ट है जो फायदे वाला साबित होगा। *(दै.भा., 28.01.21)*

देश में पहली बार सौर ऊर्जा टॉप पर

देश में पहली बार नवीनीकरणीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में सौर ऊर्जा ने पवन ऊर्जा को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2021 में कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा में 41.91 फीसदी ऊर्जा सौर ऊर्जा सयंत्रों से और 41.79 फीसदी ऊर्जा पवन ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है।

सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। प्रदेश में सबसे बड़ा करीब 2000 मेगा वाट का सौलर पार्क जोधपुर के भड़ला में हैं। सरकार द्वारा लगातार सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की वजह से दो दशक में पहली बार सूर्य की किरणों से बिजली उत्पादन ने अन्य नवीनीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों को पीछे रख दिया है।

(रा.प., 13.02.21)

बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा करंट

राज्य के 1.52 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को एक बार फिर फ्यूल सरचार्ज का झटका लगेगा। इसके जरिए बिजली कंपनियां करीब 112 करोड़ रुपए वसूलेंगी। उपभोक्ता को 7 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त राशि देनी होगी। यह राशि पिछले वर्ष अक्टूबर से दिसम्बर तक उपभोग की गई बिजली यूनिट के अनुसार जुड़ेगी।

सत्ताधारी कांग्रेस सरकार में अब तक उपभोक्ताओं पर औसतन 35 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भार आ चुका है। यह राशि तो पिछले वर्ष फरवरी में बढ़ी विद्युत दर के अतिरिक्त है। दोनों को जोड़े तो सामान्य उपभोक्ता को औसतन करीब 1.50 रुपए प्रति यूनिट ज्यादा राशि देनी पड़ेगी। *(रा.प., 07.03.21)*

बिजली चुराने वालों की खैर नहीं

अब नई तकनीक बिजली चोरी करने वालों की पहचान बता देगी। यह तकनीक चोरी करने वालों की होशियारी पर भारी पड़ेगी। यह दावा आइआइटी गांधीनगर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर नारण पिंडोरिया व उनकी टीम ने की है। दावा है कि तकनीक से बिजली कंपनियों की आय बढ़ेगी और उपभोक्ता को भी फायदा होगा।

तकनीक खुद पता लगाती है कि उपभोक्ता घरेलू है, कृषि का है या कॉमर्सियल या फिर औद्योगिक। इसके आधार पर उसकी बिजली खपत में अगर लगातार उतार-चढ़ाव होता है तो उसमें चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में इंटेलिजेंस व खपत आधारित विशिष्ट पैटर्न के जरिए यह सुनिश्चित करती है कि चोरी हो रही है या नहीं। यह तकनीक मीटर से छेड़छाड़ की भी जानकारी देती है। *(रा.प., 25.01.21)*

जांच अभियान में पकड़ी बिजली चोरी

राज्य में बिजली चोरों पर शिकंजा कसने के लिए बिजली कंपनियों ने एक दिन का जांच अभियान चला कर इतिश्री कर ली। तीनों विद्युत वितरण निगमों के सभी जिलों में एक दिन का विशेष सतर्कता जांच अभियान चलाया गया। विजिलेंस टीमों ने एक दिन में 14 हजार 228 स्थानों पर जांच की।

इस दौरान 245 स्थानों पर बिजली चोरी और 479 स्थानों पर विद्युत दुरुपयोग के मामले सामने आए। विभाग का दावा है कि आगे भी इस तरह का जांच अभियान चलेगा लेकिन कब यह अभी स्पष्ट नहीं है। जयपुर डिस्कॉम में 115 जगहों पर बिजली चोरी और 97 स्थानों पर बिजली दुरुपयोग के मामले पकड़े गए।

(रा.प., 08.03.21)

हक डकार रही बिजली कंपनियां

विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, टूटी केबल को सुधारना, खराब मीटर बदलने और अन्य परेशानी निर्धारित समय पर दूर नहीं होने पर उपभोक्ताओं को हर्जाना (क्षतिपूर्ति) देने का प्रावधान है। लेकिन बिजली कंपनियां इससे बच रही हैं। न तो प्रभावित उपभोक्ताओं को ऐसे प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है और न ही हर्जाना।

हालात यह है कि राज्य में हर्जाना लेने के लिए आगे आने वालों का यह आंकड़ा दहाई से भी कम है। बिजली कंपनियां भी केवल उन्ही मामलों में सक्रिय हैं, जिनमें कोई विद्युत दुर्घटना से मौत हो गई या शारीरिक रूप से अक्षम हो गया हो, क्योंकि ऐसे मामलों को छिपाया नहीं जा सकता। *(रा.प., 21.02.21)*

तेजी से हों जल जीवन मिशन के काम

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए। मिशन के तहत प्रदेशभर में 43 हजार 364 गांवों के करीब एक करोड़ एक लाख घरों को पेयजल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कामों में गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ग्राम स्तर पर समितियों के गठन व टेंडर प्रक्रिया के कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण हों। मिशन के तहत स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऐसे में आमजन को मिशन से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

(दै.भा. एवं रा.प., 10.03.21)

पेयजल व्यवस्था को लीकेज की 'बीमारी'

पेयजल जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर बीसलपुर से पानी जयपुर ला रही है। शहर में 40 प्रतिशत पानी प्रतिदिन लीकेज के कारण व्यर्थ बह रहा है। इसका समाधान जलदाय विभाग के इंजीनियर आज तक नहीं तलाश पाए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पानी के लीकेज की स्थिति काफी खराब है।

उधर जल भवन से लेकर रीजन कार्यालयों में पानी के नुकसान को रोकने के लिए 2007 में नॉन रेवेन्यू वाटर यानी नुकसान प्रकोष्ठ का गठन किया गया और लाखों रुपए का बजट भी दिया गया था। लेकिन प्रकोष्ठ मुख्यालय से लेकर रीजन कार्यालयों तक यह कागजों में ही सिमट कर रह गया। *(रा.प., 19.02.21)*

वाटर एक्ट हुआ कागजों में 'दफन'

जलदाय विभाग की ओर से 2016 में तैयार वाटर एक्ट का मसौदा अभी भी फाइलों में दफन है। प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की तरह वाटर एक्ट भी लागू हो तो विभाग के सालाना करोड़ों रुपए डूबत खाते में जाने से बच सकते हैं। अभी पानी के बिलों के पेटे करीब 1000 करोड़ रुपए बकाया है।

वाटर एक्ट लागू होने पर इंजीनियरों को वसूली के लिए ज्यादा अधिकार मिलते हैं। इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। जानकारों के अनुसार एक्ट में बकाया बिल की वसूली पर जाने वाले फील्ड अफसरों को पुलिस इमदाद मिलने का प्रावधान है। एक्ट में बिजली चोरी थानों की तरह वाटर एक्ट में भी कई प्रावधान किए गए हैं।

(रा.प., 17.03.21)

बदले जाएंगे औद्योगिक पेयजल मीटर

जयपुर में अमृत मिशन के तहत चार हजार से ज्यादा बंद या खराब औद्योगिक पेयजल मीटरों को बदला जाएगा। इससे खराब मीटरों से हो रहे राजस्व नुकसान को रोका जा सकेगा। जलदाय विभाग के अधिकारियों के अनुसार अमृत मिशन के तहत जयपुर में 70 हजार से ज्यादा पानी के मीटर बदले जाने हैं। इसमें औद्योगिक पेयजल कनेक्शन के मीटरों को भी शामिल किया गया है।

मिशन के तहत 50 हजार से ज्यादा बंद या खराब पानी के मीटरों को बदला जा चुका है। इसी प्रकार शहर में साढे पांच लाख मीटर जल्द लागू होने वाली मीटर पॉलिसी के तहत बदले जाएंगे। मीटर बदलने से विभाग को 50 की जगह 100 प्रतिशत राजस्व मिल सकेगा।

(रा.प., 18.02.21)

संभले नहीं तो बढ़ेगा जल संकट

राज्य सरकार ने पेयजल, घरेलू उपयोग और कृषि उपयोग सहित पांच श्रेणियों के लिए ट्यूबवेल व नलकूप खोदने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता हटाई तब से ही प्रदेश में नलकूप-बोरिंग धड़ल्ले से खोदे जा रहे हैं। विचारणीय यह है, 35 साल पहले जहां 100 लीटर पानी जमीन में जा रहा था और 35 लीटर निकाला जा रहा था, वहीं अब इसके विपरीत 100 लीटर पानी जमीन में जा रहा है और हम 140 लीटर पानी का दोहन कर रहे हैं।

जल संरक्षण विशेषज्ञों का कहना है कि भूजल को सहेजना बहुत आवश्यक हो गया है। अतिदोहित क्षेत्रों में बढ़ोतरी होने से राज्य में भू जल का 75 फीसदी क्षेत्र डार्कजोन में आ चुका है। जहां 35 साल पहले अतिदोहित ब्लॉक केवल 12 ही थे, वहीं अब अतिदोहित ब्लॉकों की संख्या 185 हो गई है।

(रा.प., 07.01.21, 22.03.21)

प्रदेश में बढ़ सकता है पानी का बिल

अप्रेल से प्रदेश में पानी के बिल में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। राजस्थान पहला प्रदेश है, जहां पानी सप्लाई और कीमत के साथ प्रोजेक्ट खर्चे का रिव्यू किए बिना ही हर साल टैरिफ बढ़ाने का नियम है। जलदाय विभाग 2017 के बाद अब नई टैरिफ लागू करेगा।

जन विरोध व चुनावी साल के कारण तीन साल से पानी के बिल में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। अब विभाग जल्द ही नए टैरिफ का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगा। नए प्रस्ताव में 15 हजार लीटर तक के जल उपभोग पर भी सीवरेज चार्ज लागू करने की कवायद है। अभी 15 हजार लीटर तक जल उपभोग पर जल शुल्क माफ है। हालांकि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही नई टैरिफ लागू होगी। *(दै.भा., 03.03.21)*

भूजल गड़बड़ाने से बढ़ा पेयजल संकट

प्रदेश में पीने के पानी का सकंट गंभीर होने के आसार सामने आने लगे हैं। राज्य में 33 में से 7 जिले ही ऐसे हैं जहां हर साल रिचार्ज से कम पानी धरती से निकाला जा रहा है। जयपुर सहित 4 जिलों में तो रिचार्ज से दोगुने से भी अधिक पानी निकाला जा रहा हे। ऐसे में बोरिंग-नलकूपों में पानी नीचे उतर रहा है।

राजस्थान देश में भूजल दोहन की मात्रा के हिसाब से चौथे स्थान पर है। नलकूप की सरकारी छूट ने डेढ़ महीने में ही धरती की कोख छलनी कर दी है। पहले प्रदेश के हर जिले में औसत एक साल में 300 ट्यूबवेल खोदे जा रहे थे। अब छूट के बाद बोरवेल मशीन दिन रात खुदाई कर रही है। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए यह छूट दी है। लेकिन सरकार को निगरानी तंत्र निश्चित तौर पर विकसित करना चाहिए। यदि ऐसे ही हालात रहे तो कुछ साल में स्थिति भयावह हो सकती है।

(रा.प., 07.01.21, 12.02.21)

प्रदेश में बढ़ गई महिला अपराध की घटनाएं

प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक माह में ही दुष्कर्म की

घटनाएं 26 प्रतिशत बढ़ी हैं। जनवरी के 30 दिन में महिलाओं से दरिंदगी के 107 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जनवरी 2021 में दुष्कर्म के 519 मामले दर्ज किए गए, जबकि दिसम्बर 2020 में 412 मामले दर्ज हुए थे।

जनवरी में दर्ज मामलों में पुलिस ने 21 मामलों को गलत माना है, जबकि 15 में चालान पेश किया गया है। बाकी 483 मामलों की जांच पेंडिंग है। प्रदेश की 57 पॉक्सो कोर्ट में 6800 केस लंबित है। जिन मामलों में पुलिस चालान पेश करती है उनमें भी न्याय बहुत धीमा है। कानून व्यवस्था कमजोर होने से दुष्कर्म व पॉक्सो से जुड़े केसों में अभियोजन में ढिलाई इसका मुख्य कारण है। डीजीपी एमएल लाठर का कहना है कि न्याय के लिए पुलिस को अभियोजन, एफएसएल व कोर्ट का सहयोग चाहिए। फरवरी में दुष्कर्म के मामले कम हुए हैं। *(दै.भा., 18.03.21)*

बढ़ता जा रहा है बालश्रम का दाग

प्रदेश में पुलिस व प्रशासन द्वारा बालश्रम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बावजूद बच्चों के माथे पर लगा बालश्रम का कलंक बढ़ता ही जा रहा है। दो साल में टॉक्स फोर्स की ओर से 4300 से ज्यादा बाल श्रमिकों को विभिन्न कार्यस्थलों से मुक्त कराया गया है। इसके बाद भी प्रदेश में बालश्रमिक लगातार श्रम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं।

प्रदेश के सभी जिलों में दो साल में 1713 से भी अधिक मामले बालश्रम के खिलाफ दर्ज हुए हैं। लेकिन कमजोर कायदों की वजह से बालश्रम को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सभी विभाग व सामाजिक संगठन बेहतर तालमेल के साथ काम करें तब ही जड़ से बालश्रम जैसी बुराई को खत्म किया जा सकता है।

(रा.प., 20.02.21)

गृहणियों के काम को कम न आंके

'यह रूढ़िवादी सोच है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, वे काम नहीं करती। इसे बदलना चाहिए। महिलाएं घरों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा काम करती हैं। उनके काम का कोई आर्थिक मोल नहीं माना जाता। यह धारणा खत्म होनी चाहिए। गृहणी बिना वेतन घर का काम करती है, जिसका परिवार के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान होता है।'

उक्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में मुआवजा राशि बढ़ाते हुए, बीमा कंपनी को 9 फीसदी ब्याज सहित 33 लाख 20 हजार रुपए उसके परिजनों को अदा करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि महिलाएं घर का पूरा प्रबंधन करती हैं, उनके काम को कम नहीं आंका जा सकता।

(रा.प., 07.01.21)

महिलाओं को नहीं मिले पूर्ण अधिकार

दुनिया में केवल 10 देश हैं, जो महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार और पूर्ण कानूनी सुरक्षा देते हैं। जबकि भारत समेत 180 देश ऐसे हैं, जो महिलाओं को समान अधिकार दे पाने में सक्षम नहीं है। वर्ल्ड बैंक की महिला, कारोबार और कानून 2021 की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार 190 देशों की सूची में बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लातविया, लक्जमबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाड़ा, पुर्तगाल और आयरलैंड ऐसे देश हैं, जो महिलाओं को आंदोलन, बोलने की आजादी, समान काम, समान वेतन का अधिकार तो देते ही हैं, साथ ही शादी करने, बच्चे पैदा करने और कारोबार चुनने तक का अधिकार देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रिपोर्ट में भारत अभी भी 123वें स्थान पर है। जबकि इस मामले में तुर्की, इजराइल और सऊदीअरब जैसे देश हमसे आगे हैं। *(दै.भा., 01.03.21)*

कोरोना में पढ़ाई भूले नौनिहाल

कोरोनाकाल ने देश के नौनिहालों की शैक्षणिक समझ-बूझ पर जबरदस्त प्रहार किया है। दस महीने तक स्कूल बंद रहने से बच्चे पिछली पढ़ाई भूल गए। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का दावा किया गया, मगर स्थिति यह है कि न केवल सरकारी बल्कि निजी स्कूलों के बच्चे भी पढ़ाई में बुरी तरह पिछड़ गए।

सबसे ज्यादा असर प्राईमरी कक्षाओं के बच्चों पर पड़ा है। प्राईमरी के 92 फीसदी बच्चे पिछली कक्षाओं में पढ़ी गई हिन्दी या अन्य भाषाई योग्यता तक नहीं पहुंचे। वहीं 82 फीसदी बच्चे पिछली कक्षाओं में पढ़ी गणितीय योग्यता को भूल गए। यह चौकाने वाले आंकड़े राजस्थान सहित पांच राज्यों में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से कोरोनाकाल के दौरान किए गए सर्वे में सामने आए है। *(रा.प., 13.02.21)*

बढ़ सकता है बाल विवाह का खतरा

दुनिया में बाल विवाह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दशक के अंत से पहले 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के एक करोड़ अतिरिक्त बाल विवाह हो सकते हैं। बालिका वधुओं में आधी से ज्यादा संख्या पांच देशों में हैं।

इन देशों में भारत भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े संगठन यूनिसेफ की रिपोर्ट 'कोविड-19 ए थ्रेट टू प्रॉग्रेस अंगेस्ट चाइल्ड मैरिज' में यह निष्कर्ष दर्ज है। यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जारी की गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों की जल्दी शादी करने और युवावस्था में होने वाली मौत के बीच भी सीधा संबंध है। बाल वधुओं के बच्चों में शिशु मृत्यु दर बढ़ने का खतरा भी अधिक रहता है। *(दै.भा., 10.03.21)*

इलाज से लेकर प्रसव तक सुविधा

निसंतान दंपती के लिए जयपुर सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में पहला सरकारी आईवीएफ सेंटर स्थापित होगा। इसमें निसंतानता के इलाज से लेकर प्रसव तक की आधुनिक सुविधा एक ही छत के नीचे मिल सकेगी। इसमें आउटडोर, इनडोर, ऑपरेशन, काउंसलिंग, जांच और प्रसव शामिल है।

अस्पताल में इसके लिए एसएमएस एडवांस असिस्टेड रिपोरडक्टिव टेक्नोलोजी (स्मार्ट सेंटर) बनाया जा रहा है। चिकित्सालय में जल्द ही यह सुविधा मिलने लगेगी। एसएमएस के चरक भवन स्थित राजकेयर आईवीएफ सेंटर को अब यहां शिफ्ट किया जा रहा है। *(दै.भा., 04.02.21)*

वाहनों की गति को कम करके सड़क दुर्घटनाओं को किया जा सकता है नियंत्रित

'वाहनों की गति कम करने से सड़क दुर्घटना की घटनाओं को रोका जा सकता है, क्योंकि वाहनों की गति में औसतन एक किलो मीटर की वृद्धि से ऐसी घटनाओं में तीन प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।'

'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा आयोजित वेबिनार में विशेषज्ञों ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गति नियंत्रण तंत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए यह विचार रखे। इस वेबिनार का अयोजन छठे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में किया गया था। वेबिनार के प्रारंभ में जॉर्ज चेरियन, निदेशक, 'कट्स' इंटरनेशनल ने कहा कि सड़कों पर हर किसी को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। राजमार्ग मंत्रालय 2019 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सालाना लगभग 1.51 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वाहन गति को कम करने से सड़क दुर्घटनाओं और इसके होने वाले प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है।

वेबिनार में हिस्सा लेते हुए ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इनक्यूबेटर के भारत समन्वयक नलिन सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार और सड़क प्रवर्तन एजेंसियों को राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में मोटर वाहनों के लिए गति सीमा को कम करने पर विचार करना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उप सचिव गौरव एच. गुप्ता ने सड़क सुरक्षा पर सरकार द्वारा की गई पहल को रेखांकित करते हुए मंत्रालय द्वारा उठाए गए सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बच्चों के मन में सड़क पर सुरक्षित व्यवहार पैदा करने के लिए एक स्कूली पाठ्यक्रम पर काम कर रहा है।

वेबिनार में आईआईटी, खड़गपुर के प्रो. भार्गव मैत्रा ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात प्रबंधन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत में साक्ष्य आधारित गति प्रबंधन पर अधिकारियों और नीति निर्माताओं को विचार मंथन करना चाहिए। केरल सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक टी एलनगोवन ने केरल सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए अपनाई गई गति प्रबंधन तकनीकों का खुलासा करते हुए विभिन्न यातायात उपकरणों के बारे में बताया। वेबिनार में वीरेन्द्र राठौड़, जिला प्रबंध अधिकारी, भीलवाड़ा ने अपने अधिकार क्षेत्र में वाहनों की गति सीमा को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए नवाचारों की जानकारी दी।

ब्लैक स्पॉट के आसपास बनेंगे ट्रॉमा सेंटर

प्रदेशभर में 800 ब्लैक स्पॉट के कारण सड़क हादसों में हर साल करीब 10000 लोगों की मौत हो जाती है। अब हादसों में घायल लोगों को तत्काल इलाज देने के लिए वाहनों के चालान से मिले 10 करोड़ रुपए से जयपुर समेत प्रदेश में 40 ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा फंड से यह पैसा स्वास्थ्य विभाग को दे दिया है। राजस्थान में हर साल करीब 23 हजार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन हादसों में 10 हजार लोगों की मौत हो जाती है। ये ट्रॉमा सेंटर 28 जिलों में शुरू किए जाएंगे। इसके लिए उन गांवों और कस्बों को चुना गया है, जिसके आसपास सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं।

परिवहन विभाग ने हादसों का पूरा डाटा भी स्वास्थ्य विभाग को दे दिया है। परिवहन विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. लक्ष्मीनिधि पांडे का कहना है कि 800 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं उन्हीं के आसपास ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। *(दै.भा., 22.06.21)*

घायलों का तत्काल उपचार अनिवार्य

सड़क दुर्घटना में घायलों को नजदीकी निजी अस्पतालों में पैसे जमा कराए बिना अब तत्काल इलाज उपलब्ध हो सकेगा। घायल का इलाज करने से मना करने के मामलों में निजी अस्पताल एवं डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार घायल व्यक्ति को लोग पास के निजी अस्पताल में ले जाते हैं जहां पहले रजिस्ट्रेशन और ईलाज के लिए रुपए जमा कराने को कहा जाता है। इससे घायल व्यक्ति के जीवन का खतरा बढ़ जाता है। अब कोई निजी अस्पताल व डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकेगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। घायल को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

(रा.प. एवं दै.भा., 07.01.21)

लाल बत्ती पर अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाएं

रोडवेज प्रशासन ने सभी डिपो मैनेजर को निर्देश दिए हैं कि सड़क पर लाल बत्ती से हरी बत्ती होने तक बस चालक अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाएं। यह निर्देश कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) के एक पत्र के आधार पर दिए हैं। गौरतलब है कि 'कट्स' ने रोडवेज बस चालकों की ओर से बसों का अनावश्यक हार्न बजाने के खिलाफ अभियान शुरू कर रखा है। संस्था के अनुसार सड़क पर रोडवेज बस चालक वाहन चलाते समय अनावश्यक हॉर्न बजा रहे हैं।

इसकी वजह से सड़कों पर बढ़ती वाहन संख्या के साथ बढ़ते शोर से न केवल अन्य वाहन वालकों, अपितु राहगीरों व सड़क किनारे बसे घरों में रहने वालों का जीवन दुश्वार होता है। रोडवेज प्रशासन इस पर वाहन चालकों को अनावश्यक हार्न नहीं बजाने के निर्देश दिए हैं।

(रा.प., 19.03.21)

सड़क हादसों में घायलों का मुफ्त इलाज

सड़क हादसों में घायलों का अब देशभर में निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम में मुफ्त इलाज हो सकेगा। उन्हें अस्पताल पहुंचाने या दूसरी जगह ट्रांसफर करने का खर्च भी मिलेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जल्द राष्ट्रीय कैशलेस ट्रीटमेंट योजना लागू करने जा रहा है। इसमें हादसों के घायलों को अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

केंद्र सरकार ने हादसे के एक घंटे में घायलों के मुफ्त इलाज के लिए 21 हजार निजी अस्पताल व नर्सिंग होम सूचीबद्ध किए हैं। योजना के तहत देशभर में कहीं भी सड़क हादसों के घायलों का निजी अस्पतालों में डेढ़ लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। स्थाई अपंगता या इलाज के दौरान मौत पर पांच लाख रुपए का मुआवजा देय होगा। *(रा.प., 25.01.21)*

उपभोक्ता फैसले

लापरवाही से विवाहिता की मौत
प्रसूति गृह को देना होगा ब्याज सहित हर्जाना

राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बैंच बीकानेर में मुकेश कुमार नाहटा ने बीकानेर के प्रताप प्रसूति गृह, टोडा हाउस के खिलाफ अपील दर्ज कराई। मामले के अनुसार परिवादी मुकेश कुमार व उसकी पत्नी अनुपमा ने चार साल तक संतान नहीं होने पर प्रताप प्रसूती गृह में संपर्क किया। अस्पताल प्रबंधन ने 14 जुलाई 2007 को अनुपमा की लेप्रोस्कोपी की, लेकिन इससे पहले होने वाली जांचें नहीं की।

इस दौरान सही जगह जांच निडल नहीं डालने के चलते अनुपमा को इंजरी हो गई और खून बहने लगा। इसके बाद ऑपरेशन भी कर दिया गया। जांच निडल की स्प्रिंग को लापरवाही से पीछे खेंचने से उसका नुकिला सिरा आंत तक चला गया और नसें कट गईं। इससे अनुपमा की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मामला उपभोक्ता मंच में दर्ज कराया था, लेकिन फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर यह अपील दर्ज की है।

मामले की सुनवाई पर आयोग ने पाया कि अस्पताल में इलाज के पर्याप्त संसाधन तक नहीं थे। इसके अभाव में चिकित्सकीय लापरवाही भी बरती गई। राज्य आयोग ने प्रताप प्रसूति गृह पर 15 लाख 21 हजार 500 रुपए का हर्जाना लगाया। साथ ही हर्जाना राशि पर 15 जुलाई 2009 से 9 फीसदी ब्याज भी देने के आदेश दिए हैं।

(रा.प. एवं दै.भा., 06.01.21)

मोतियाबिंद के आपरेशन में लापरवाही
अस्पताल को देना होगा ब्याज सहित हर्जाना

राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग में चुरू निवासी भंवर सिंह ने डॉ. रणजीत सिंह बेनीवाल एवं अस्पताल के खिलाफ अपील दर्ज कराई। मामले के अनुसार परिवादी भंवर सिंह रेलवे में कांटेवाला के पद पर कार्यरत थे। रेलवे अस्पताल की सलाह पर उसने डॉ. रणजीत सिंह को अपनी आंखे दिखाई। डॉक्टर ने जांच के बाद नेत्रदृष्टि कमजोर बताते हुए छह माह बाद ऑपरेशन करवाने की सलाह दी, लेकिन रेलवे ने उन्हें फिटनेस जारी नहीं किया और उन्होंने दुबारा चैकअप करवाया। इस पर डॉक्टर ने 18 हजार रुपए लेकर ऑपरेशन करके विदेशी लेंस लगाने की बात कही। ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही के कारए उनकी आंख की पुतली खराब हो गई। जयपुर और दिल्ली एम्स तक दिखाने के बाद भी उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। इसके चलते उनकी नौकरी में ग्रेड भी कम कर दी गई। भंवर सिंह ने राज्य आयोग में चुनौती देते हुए जिम्मेदार अस्पताल व डॉक्टर्स से क्षतिपूर्ति राशि की मांग की।

आयोग ने मामले की सुनवाई पर अस्पताल व डॉक्टर्स को सेवादोष और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानते हुए इसके लिए दोषी अस्पताल व डॉक्टर्स पर बीस लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही हर्जाना राशि पर 27 जनवरी 2016 से नौ प्रतिशत ब्याज भी अदा करने के आदेश दिए हैं।

(दै.भा., 07.02.2021)

एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों में घटाई ट्रांस फैट की मात्रा

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनियाभर में हर साल करीब 5.4 लाख मौतें वसायुक्त अम्ल (ट्रांस फैटी एसिड) के सेवन से होती हैं। यह सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसके ज्यादा सेवन से हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी बीमारियों से मौत का ज्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा यह खराब याददाश्त और डिमेशिया के खतरे से भी जुड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस खतरे को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2023 तक खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट्स के उन्मूलन की मांग की है।

इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा को घटाया है। उसने एक संशोधन के जरिए ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा 5 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर दिया है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक जनवरी 2021 से तेल और फैट में ट्रांस फैटी एसिड की अधिकतम सीमा वजन में 3 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी। वर्ष 2022 तक इस सीमा को घटाकर 2 फीसदी किए जाने पर भी मंथन जारी है।

संशोधित विनियमन खाने वाले रिफाइन तेल, वनस्पति, मार्जरीन और अन्य कुकिंग के माध्यमों एवं औद्योगिक प्रक्रिया के तहत तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों पर लागू होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो या तो प्राकृतिक या औद्योगिक स्त्रोत से मिलते हैं। यह नया विनियमन तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है।

प्रदीप एस. महता स्कोच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित

प्रदीप एस. महता, महासचिव, 'कट्स' इन्टरनेशनल को सार्वजनिक नीति में उनके सराहनीय योगदान के लिए 'स्कोच चैलेंजर अवार्ड' से सुरेश प्रभु, सदस्य, राज्य सभा और जी 20 शेरपा द्वारा 16 जनवरी 2021 को सम्मानित किया गया। सुरेश प्रभु ने सार्वजनिक नीति क्षेत्र में जीवंतता लाने में उनकी भूमिका की सराहना की।

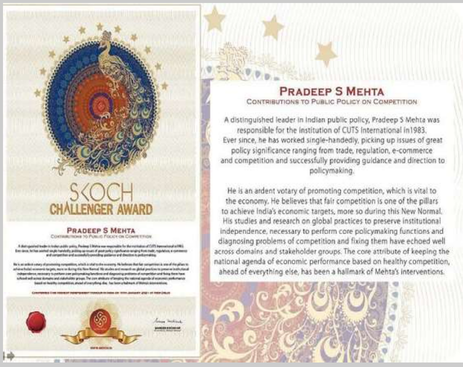

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259
फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)